"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुक्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001."



पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ्/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 189 🛚

रायपुर, मंगलवार, दिनांक 31 मार्च 2020 — चैत्र 11, शक 1942

छत्तीसगढ़ विधान समा सचिवालय

रायपुर, गुरूवार, दिनाक २६ मार्च, २०२० (चैत्र ६, १९४२)

क्रमाक—5053 / वि.स. / विधान / 2019. — छत्तीसगढ़ विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य सचालन सबधी नियमावली के नियम 64 के उपबंधों के पालन में पिडत सुदर शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय (सशोधन) विधेयक, 2020 (क्रमाक 12 सन् 2020) जो गुरूवार, दिनाक 26 मार्च, 2020 को पुर स्थापित हुआ है, को जनसाधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है।

हस्ता. / —

(चन्द्र शेखर गंगराड़े) प्रमुख सचिव

छत्तीसगढ विधेयक

(क्र. 12 सन् 2020)

पण्डित सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़ (संशोधन) विधेयक, २०२०

पण्डित सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़ अधिनियम, २००४ (क्र. २६ सन् २००४) को और सशोधित करने हेत् विधेयक।

भारत गणराज्य के इकहत्तरवे वर्ष में छत्तीसगढ़ विधान मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो —

संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारंभ.

1.

- (1) यह अधिनियम पण्डित सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ (सशोधन) अधिनियम, २०२० कहलायेगा ।
- (2) इसका विस्तार सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य मे होगा ।
- (3) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा।

धारा 9 का संशोधन.

- . पण्डित सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ अधिनियम, २००४ (क्र. २६ सन् २००४) (जो इसमे इसके पश्चात मूल अधिनियम के रूप मे निर्दिष्ट हैं), धारा ९ मे,—
 - (क) उप—धारा (1) में, शब्द ''कुलाधिपति द्वारा'' के पश्चात्, शब्द ''राज्य शासन के परामर्श के पश्चात्'' के स्थान पर्, शब्द ''मित्र—परिषद् के निर्णय के अनुसार'' प्रतिस्थापित किया जाये।
 - (ख) उप-धारा (२) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात्-
 - ''(2) कुलाधिपति एक खोज समिति गठित करेगा, जिसमे निम्नलिखित व्यक्ति शामिल होगे, अर्थात् —
 - (एक) कार्य परिषद् द्वारा अनुशसित एक व्यक्ति,
 - (दो) राज्य सरकार द्वारा अनुशसित राज्य के किसी भी अन्य विश्वविद्यालय के कुलपति, और
 - (तीन) राज्य सरकार द्वारा नामनिर्देशित एक व्यक्ति, कुलाधिपति, उपरोक्त तीन व्यक्तियों में से एक को समिति के अध्यक्ष के रुप में नियुक्त करेगा ।''
 - (ग) उप–धारा (११) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात्–
 - "(11) इस अधिनियम में अतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी,-
 - (एक) कुलपति अपने पद पर तब तक बना रहेगा, जब तक मत्रि—परिषद् उसकी सेवा लेना उचित समझे,
 - (दों) मत्रि—परिषद् के निर्णय के अनुसार कुलाधिपति, कुलपति को किसी भी समय उसके पद से तत्काल प्रभाव से हटा देवेगे,
 - (तीन) मित्र—परिषद्, कुलपित की नियुक्ति की प्रक्रिया को किसी भी समय निरस्त कर सकती है।"
 - (घ) उप–धारा (12) का लोप किया जाये।
 - (ड.) उप—धारा (13) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् "(13) उप—धारा (11) के अधीन आदेश मे विनिर्दिष्ट की गई तारीख से कुलपति का पद रिक्त हो जायेगा।"

उद्देश्य और कारणों का कथन

यत, पण्डित सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़ अधिनियम, 2004 (क्र. 26 सन् 2004) के प्रावधानों में, विश्वविद्यालय के प्रशासन के लिये बेहतर प्रावधानों का उपबंध करने के प्रयोजन हेतु, संशोधन किया जा रहा है।

और यत, राज्य सरकार ने विश्वविद्यालय के कार्यों को सुगम बनाने एवं एकरुपता लाने को दृष्टिगत रखते हुये, पण्डित सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़ अधिनियम, 2004 (क्र. 26 सन् 2004) में संशोधन करने का निर्णय लिया हैं।

अतएव, उपरोक्त उद्देश्यो की प्राप्ति की दृष्टिगत रखते हुये, पण्डित सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़ अधिनियम, २००४ (क्र. २६ सन् २००४) मे सशोधन करना आवश्यक है ।

अत यह विधेयक प्रस्तुत है।

रायपुर दिनाक 25–03–2020 उमेश पटेल उच्च शिक्षा मन्त्री (भारसाधक सदस्य)

उपाबन्ध

पिडत सुदरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़ अधिनियम, 2004 (क. 28 सन् 2004) की धारा 9 में उप–धारा (14) का सुसगत उद्धरण –

कुलपित की मृत्यु, उसके पदत्याग, छुट्टी, रूग्णता के कारण या अन्य कारण से उसका पद रिक्त होने की दशा में, जिसमें अस्थायी रिक्ति भी सम्मिलित हैं, तो कुलाधिपित द्वारा उस प्रयोजन के लिये नाम निर्देशित किया गया किसी भी सकाय का सकायाध्यक्ष कुलपित के रूप में उस तारीख तक कार्य करेगा जब तक कि उपधारा (1) या उपधारा (7) के अधीन नियुक्त किया गया कुलपित अपना पद यथास्थित ग्रहण या पुन ग्रहण न कर ले।

परतु इस उपधारा के अधीन अनुध्यात किया गया इतजाम छ माह से अधिक कालावधि के लिये चालू नहीं रहेगा।

> चन्द्र शेखर गगराड़े प्रमुख सचिव छत्तीसगढ़ विधान सभा.